

सौभाग्य योजना

- प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धता प्रदान करना है।
- इस योजना में भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को धन उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके तहत राज्यों को 31 दिसंबर 2018 तक घरेलू विद्युतीकरण के कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था, इस योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली कनेक्शन हेतु लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के आंकड़ों द्वारा की जाती है, हालांकि इस जनगणना के तहत जो बीपीएल परिवार नहीं आते उन्हें भी 500 रु. के भुगतान पर बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
- देश में सुदूर व दुर्लभ क्षेत्रों के लिए जहां विद्युत उपलब्धता नहीं है, ऐसे घरों को बैटरी बैंक के साथ 200 से 300 वॉट का सौर ऊर्जा पैक जिसमें 5 एलईडी लाइट, पॉवर फैन व पॉवर प्लग दिए जाते हैं। इस पैकेज में 5 वर्ष तक का रख-रखाव भी शामिल है।

सौभाग्य योजना के लक्ष्य

1. सभी इच्छुक घरों तक बिजली पहुंचाना
2. घरों में मिट्टी के तेल का उपयोग बंद कर पर्यावरण को सुधारना
3. शिक्षा सेवाओं में सुधार करना
4. बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करना
5. रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाना
6. आर्थिक गतिविधियों द्वारा नौकरियों में वृद्धि करना
7. महिलाओं के जीवन में गुणात्मक सुधार करना

योजना के कार्यान्वयन -

योजना के आसान व त्वरित कार्यान्वयन जैसे घरेलू सर्वेक्षण के लिए मोबाइल एप जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर लाभार्थियों की पहचान की जाती है। आवेदक की तस्वीर और पहचान प्रमाण के साथ बिजली कनेक्शन के लिए उनके आवेदन को पंजीकृत किया जाता है।

ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत, सार्वजनिक संस्थानों को पूरे दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र इकट्ठा करने, बिल वितरित करने और पंचायती राज संस्थानों और साथ में शहरी स्थानीय निकायों के परामर्श से राजस्व एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है।

- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC) को पूरे देश में योजना के संचालन हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया है।

सौभाग्य योजना से संबंधित कुछ आंकड़े

- अक्टूबर 2017 से अब तक 12.39 करोड़ से अधिक परिवारों का विद्युतीकरण हुआ है।
- 29 राज्यों में घरेलू विद्युतीकरण में 100 फीसदी सफलता मिली है। इनमें म.प्र., त्रिपुरा, बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड, मिजोरम, सिक्किम और तेलंगाना शामिल है।
- आपको बता दें, कि इस योजना के तहत केन्द्र 60 फीसदी अनुदान देता है। जो विशेष राज्यों के लिए बढ़कर 85 फीसदी हो जाती है, शेष राशि राज्यों को लगानी होती है।
- निजी क्षेत्र के सभी डिस्कॉम (विद्युत वितरण क.) राज्य विद्युत विभाग और सहकारी समितियों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

- विद्युत अधिनियम तथा 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतकीरण योजना द्वारा सौभाग्य योजना को बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया था।

मूल्यांकन

योजना की कमियां

- बिजली वितरण कंपनियों, राज्य व केंद्रीय स्तर पर नौकरशाहों व कई इंजीनियरों के प्रयास इस योजना को सफल करने के लिए शामिल हैं, फिर भी बिजली का सार्वभौमिक विस्तार नहीं हो पाया है। बिजली कनेक्शन दिए जाने के बाद भी बिजली का प्रवाह नहीं हो पाया है।
- बिजली सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार, छह राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सर्वे किया गया जिसमें यह बात सामने आई की बिजली कनेक्शन के बाद भी बिजली की आपूर्ति नहीं हुई। बिजली आपूर्ति के औसत घंटे 2015 में 12 घंटे थे जिसे 2018 में बढ़ाकर 16 घंटे किया गया, लेकिन अभी भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं।
- इसी प्रकार पिछले 3 वर्षों में कम वोल्टेज की समस्या बढ़ी हैं। लगभग एक चौथाई ग्रामीण परिवार को अभी भी माह में कम से कम पांच दिनों के लिए कम वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ा।
- बुनियादी ढांचे की कमी के कारण ग्रामीण आबादी ने एक माह में कम से कम 24 घंटे तक अप्रत्याशित ब्लैकआउट की सूचना दी। छह राज्यों के विद्युतीकरण ग्रामीण परिवारों के लगभग 27% लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं की गई।

बिजली आपूर्ति सुधार हेतु उठाए गए कदम -

- भारत में बिजली उपयोगकर्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वास्तविक बिजली आपूर्ति के समय की निगरानी की आवश्यकता है। वर्तमान में बिजली आपूर्ति निगरानी का कोई प्रावधान नहीं है। इस कार्य को बिजली वितरण कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए। इस संबंध में सरकार की योजना 'स्मार्ट मीटर' इस निगरानी में सक्षम है।
- डिस्कॉम या वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत गुणवत्ता में सुधार व रख-रखाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- महाराष्ट्र ने स्थानीय स्तर पर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ग्रामीण स्तर पर समन्वय का प्रयास किया। इसी तरह ओडिशा ने ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के रख-रखाव के लिए विभिन्न शाखाओं से समन्वय स्थापित किया। इस तरह के समाधान अन्य राज्यों द्वारा भी किए जाने चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

- दशकों से राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्रों में बिजली के साथ पानी का वादा करती हैं। पूर्वोत्तर राज्य का गांव 'लीसांग' विश्व भर में सुर्खियों में आया क्योंकि यह भारत का आखिरी गांव था जहां बिजली पहुंची थी। यह गांव किस राज्य में स्थित है।

(a) मणिपुर

(b) अरुणाचल प्रदेश

(c) नागालैण्ड

(d) मिजोरम

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न - भारत में विद्युत आपूर्ति हेतु 'सौभाग्य योजना' द्वारा 100 फीसदी विद्युतीकरण के बाद भी बिजली की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। इसके लिए उत्तरदायी कारणों व उपायों पर चर्चा करें।